भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2721

मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ओएनडीसी

2721. श्री प्रवीन खंडेलवालः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे शहरी व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को एकीकृत करने में डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क की भूमिका का अध्ययन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) महानगरीय व्यावसायिक जिलों से कितने विक्रेताओं को इस नेटवर्क से जोड़ा गया है; और

(ग) प्रतिस्पर्धा, मूल्यों में पारदर्शिता और उपभोक्ता के विकल्प पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी), साइलो में काम करने वाले पारंपरिक ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के विपरीत, एक ओपन ईकोसिस्टम बनाता है, जहां विक्रेता प्लेटफॉर्म-विशिष्ट नियमों और शर्तों की सीमाओं में बंधे बिना कई प्लेटफार्मों से ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। ओएनडीसी यह सुनिश्चित करता है कि छोटे व्यवसाय, स्थानीय व्यापारी और एमएसएमई उभरते हुए ई-कॉमर्स वातावरण के डिजिटल दायरे से बाहर न छूट जाएं और इन वर्गों को ई-कॉमर्स के परिवेश में ओपन प्रोटोकॉल के माध्यम से निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण रूप से खोजे जाने के अवसर प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाता है। यह ओपन प्रोटोकॉल, आकार, पैमाने या डिजिटल विशेषज्ञता की शर्तों के बिना नेटवर्क पर मौजूद सभी विक्रेताओं को समान रूप से विजिबल बनाता है। विक्रेता-पक्ष ऐप्स अपने पूर्ण कैटलॉग को सभी खरीदार-पक्ष ऐप्स के लिए खोजे जाने योग्य बनाते हैं, जबकि खरीदार-पक्ष वाले ऐप्स, खोज परिणामों को छांटने या सूचीबद्ध करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख मापदंडों की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जिससे विक्रेता अपनी रैंकिंग को बेहतर ढंग से समझ सकें और इसमें सुधार कर सकें। सभी नेटवर्क प्रतिभागियों द्वारा अपनाए गए साझा मुक्त

स्पेसिफिकेशन, पारदर्शिता में वृद्धि करते हैं तथा अपारदर्शी या पक्षपाती सूचीकरण पद्धतियों को रोकते हैं।

इसके अतिरिक्त, एमएसएमई मंत्रालय की व्यापार सक्षमता और विपणन (टीम) स्कीम, ओएनडीसी के माध्यम से, एसएमई, छोटे विक्रेताओं, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कारीगरों, ग्रामीण उद्यमियों और स्थानीय खुदरा विक्रेताओं द्वारा डिजिटल कॉमर्स को अपनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत, इन छोटे विक्रेताओं को डिजिटल साक्षरता, जागरूकता, कैटेलॉगिंग और ऑनबोर्डिंग की दिशा में सहायता प्रदान की जाती है। इसके 50 प्रतिशत लाभार्थी, महिलाओं के नेतृत्व वाले एसएमई में से बनाने का लक्ष्य निर्धारित करके इसमें समावेशिता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

(ख): 9 दिसंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, देशभर के 630 से अधिक शहरों और कस्बों के कुल 1.16 लाख से अधिक खुदरा विक्रेता ओएनडीसी पर लाइव हैं। हालांकि विक्रेताओं के महानगरीय व्यवसाय का जिला-वार वर्गीकरण तैयार नहीं किया जाता है।

(ग): ओएनडीसी नेटवर्क, एकाधिक क्रेता तथा विक्रेता-पक्ष एप्लीकेशनों के बीच अंतर-संचालन को सक्षम करके छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करता है, जिससे डिजिटल कॉमर्स में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। समान उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराने वाले एकाधिक प्लेटफार्मों की मौजूदगी होने से, उपभोक्ताओं के लिए कीमतों के मामले में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त, जैसे-जैसे विभिन्न आकारों और विविध भौगोलिक क्षेत्रों के विक्रेता इस नेटवर्क पर सुलभ होते जाते हैं, उपभोक्ता, उत्पादों और सेवाओं के मामले में व्यापक चयन से लाभान्वित होते हैं, जिससे अधिक जानकारी आधारित और प्रतिस्पर्धी विकल्प चयन संभव होता है।

****